

प्रेषक,

डी0एस0 गब्याल,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 27 दिसम्बर, 2016

विषय- प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जेदारों को विनियमित किये जाने हेतु सर्किल रेट का निर्धारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया, उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 804/XVIII(II)/2014- 07(46)/2008 दि0-18 जुलाई, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस शासनादेश के विभिन्न प्रस्तारों में वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जों एवं पट्टेदारों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करते हुये विनियमितीकरण की कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

2- इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जेदारों एवं पट्टेदारों के विनियमितीकरण की कार्यवाही वर्ष 2000 के सर्किल रेट के आधार पर निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-804/XVIII(II)/2014-07(46)/2008 दि0-18 जुलाई, 2016 के संगत प्रस्तारों में नजराने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट की दर के स्थान पर वर्ष 2000 के सर्किल रेट के अनुसार विनियमितीकरण की कार्यवाही की जाय, तथा उक्त सन्दर्भित शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय,

(डी0एस0गब्याल)
सचिव।

संख्या-3017/XVIII(II)2016-07(46)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, गढवाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)

अपर सचिव।